



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 334]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 2, 1983/श्रावण 11, 1905

No. 334]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 2, 1983/SRAVANA 11, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक विकास विभाग)

आवेश

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1983

का० आ० 549(अ)/18कक/आई० डी० आर० ए०/83.—  
भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 18(अ) 18कक/आई० डी० आर० ए०/79 तारीख 6 जनवरी 1979 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) आंध्र प्रदेश राज्य के श्री काकुलम जिले के मीनानगरम् में चीनी का विनिर्माण करने वाले मैसर्स श्रीराम शुगरम् एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के एकक का (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन 5 जनवरी 1982 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और निजाम शुगर फैक्ट्री लिमिटेड को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध सहाय करने के लिये प्राधिकृत किया गया था।

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 7(अ)/18कक/आई० डी० आर० ए०/82 तारीख 5 जनवरी 1982 का आ० 551 (अ)/18कक/आई० डी० आर० ए०/82 तारीख 2 अगस्त 1982 और का० आ० 80(अ)/18कक/आई० डी० आर० ए०/83 तारीख 2 फरवरी 1983 द्वारा उक्त आदेश को 2 अगस्त 1983 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है अवधि के लिए जारी रखा गया था;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम 2 फरवरी, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है छह मास की और अवधि के लिए निजाम शुगर फैक्ट्री लिमिटेड के प्रबन्ध के अधीन बना रहे;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करने हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 2 फरवरी, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा० सं० 1(11)/78-मी० य० एम०]

**MINISTRY OF INDUSTRY**

(Department of Industrial Development)

**ORDERS**

New Delhi, the 2nd August, 1983

S.O. 549(E)/18AA/IDRA/83.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 18(E)/18AA/IDRA/79, dated the 6th January, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the unit of Messrs Sri Rama Sugars and Industries Limited manufacturing sugar at Seethanagaram in District Sriakulam in the State of Andhra Pradesh (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) was taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of three years upto and inclusive of the 5th January, 1982, and the Nizam Sugar Factory Limited was authorised to take over the management of the said Industrial Undertaking;

And, whereas, by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 7(S)/18AA/IDRA/82, dated the 5th January, 1982, S.O. 551(E)/18AA/IDRA/82 dated the 2nd August, 1982 and S.O. 80(E)/18AA/IDRA/83 dated the 2nd February, 1983, the said Order was continued for a period upto and inclusive of the 2nd August, 1983;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Industrial Undertaking should continue under the management of the Nizam Sugar Factory Limited for a further period of six months upto and inclusive of the 2nd February, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of six months upto and inclusive of the 2nd February, 1984.

[F. No. 4/11/78-CUS]

का० आ० 550(अ)/18चख/आई०डी०आर०ए०/83.—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 902 (अ)/18-चख/आई० डी० आर० ए०/80 तारीख 21 नवम्बर 1980 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) (उद्योग विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा

(1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की गयी कि उक्त आदेश के जारी किए जाने की तारीख से ठीक पहले प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण-पत्रों करारों, परिनिर्धारणों, पंचाटों, स्थायी आदेश या अन्य लिखतों का (उनसे भिन्न जो 6 फरवरी, 1979 के पश्चात् किए गए हैं, हुए हैं या प्रवृत्त हुए हैं) जिनका आन्ध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले के सीतानगरम् में चीनी का विनिर्माण करने वाले मैसर्स श्रीराम शूगर्स एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एकक या उक्त एकक का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी एक पक्षकार है या जो उक्त एकक या कम्पनी को लागू हो, प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त आदेश के जारी किए जाने की तारीख से पहले उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत सभी अधिकार, विशेषधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे;

और, उक्त आदेश की अवधि को भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 820(अ) 18चख/आई० डी० आर० ए०/81, तारीख 20 नवम्बर, 1981 का० आ० 8(अ)/18चख/आई० डी० आर० ए०/81 तारीख 5 जनवरी, 1982 का० आ० 552(अ)/18चख/आई० डी० आर० ए०/82 तारीख 2 अगस्त, 1982 और का० आ० 80(अ)/18चख/आई० डी० आर० ए०/83, तारीख 2 फरवरी, 1983 द्वारा 2 अगस्त, 1983 तक की जिसमें, यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए बढ़ाया गया था;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि के सभी मामलों की बाबत (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रति प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं 2 फरवरी, 1984 तक का, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए बढ़ा दिया जाए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश को अवधि को सभी मामलों की बाबत (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रति प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं) 2 फरवरी, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, अवधि के लिए बढ़ाती है।

[फा० सं० 4(11)/78-सी०यू०एस०]

ए० पी० सरवन, संयुक्त सचिव

S.O. 550(E)/18FB/IDRA/83.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development), No. S.O. 902(E)/18FB/IDRA/80, dated the 21st November, 1980 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exer-

cise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those which have been entered into, arrived at or come into force after the 6th January, 1979) to which the unit of Messrs Sri Rama Sugars and Industries Limited, manufacturing sugar at Seethanagaram in the District of Srikakulam in the State of Andhra Pradesh or the company owning the said unit is a party or which may be applicable to the said unit or company shall remain suspended for a period of one year and all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the date of issue of the said order shall remain suspended for the said period :

And, whereas, the duration of the said Order was extended for a further period upto and inclusive of 2nd August, 1983, by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos.

S.O. 820(E)|18FB|IDRA|81, dated the 20th November, 1981, S.O. 8(E)|18FB|IDRA|82, dated the 5th January, 1982, S.O. 552(E)|18FB|IDRA|82, dated the 2nd August, 1982 and S.O. 81(E)|18FB|IDRA|83, dated the 2nd February, 1983;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto and inclusive of the 2nd February, 1984, in respect of all matters (except those relating to secured liabilities to banks and financial institutions);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period upto and inclusive of 2nd February, 1984, in respect of all matters (except those relating to secured liabilities to banks and financial institutions).

[F. No. 4(11)|78-CUS.]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.

